Dependence on import of fertilizers

*62. SHRI NARESH AGRAWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government has taken note of country's dependence on import of fertilizers;

(b) if so, the steps Government has taken to address the issue;

(c) whether Government has formed any joint venture with foreign companies/ countries to increase production of fertilizers;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government is fully aware that country is dependent on imports of fertilizers. In case of Urea, the country is import dependent to the extent of about 25% of its total requirement. In potash sector, the country is fully import dependent as there are no known reserves of Potash within the country. In Phosphatic sector, country is import dependent to the extent of 90%, either in the form of finished fertilizers or its raw material, as there are very limited reserves of rock phosphates.

(b) to (e) The gap between requirement and domestic availability of fertilizers is being met through imports. In order to reduce import dependence, the fertilizer companies are encouraged to form Joint Ventures (JV) abroad in resource rich countries. Such JVs may be in the form of investment in production facilities with long term buy back arrangement. The Government is also encouraging its Public Sector Undertakings for acquisition of fertilizer mineral assets abroad.

In Urea Sector, at the behest of the Government, a JV namely OMIFCO (Oman India Fertilizers Company) has been formed in Oman with long term off-take agreement of 16.5 LMT of Urea and 2.4 LMT of Ammonia at a fixed price.

In order to attract new domestic investment in Urea sector, Government has notified a New Investment Policy on 2nd January, 2013. The policy also encourages JVs abroad and off take arrangements from such JVs in countries rich in natural gas.

List of existing JVs abroad in Urea and Phosphatic and Potassic sector is given in the Statement.

Statement

List of existing Joint Venture

Sl. No	JV Project-Country	Entities	Product	Input tie up/ Model	Off take arrangement
1	2	3	4	5	6
JV in Urea Sector					
1.	Oman India Fertilizer Co. (OMIFCO), Oman	Oman Oil Co. (OOC-50%), IFFCO (25%) and KRIBHCO (25%)	16.52 lakh MT Urea and 2.48 lakh MT Ammonia	Gas tie from OCC	— Urea Off-take Agreement (UOTA) by GoI for off take of entire quantity on fixed price — Ammonia Off-take Agreement (AOTA) by IFFCO for off take of entire ammonia.
JV in P&K Sector					
1.	ICS Senegal, Senegal	ICS Senegal and IFFCO consortium	5.5 lakh MT phosphoric acid	Rock phosphate mining at Louga is integral to the joint venture	Off take agreement by IFFCO for off take of entire quantity of phosphoric acid.
2.	INDO-JORDAN Chemicals Company (UC), Jordan	JPMC (Jordan and and SPIC (India)	2.24 lakh MT phosphoric acid	—	Off-take agreement on phosphoric acid by SPIC.

1	2	3	4	5	6
3.	JPMC-IFFCO JV, Jordan	JPMC & IFFCO	4.8 lakh MT phosphoric acid	Rock supplied by JPMC at international price	Off take agreement by IFFCO for off take of entire qty. of phos acid.
4.	IMACID, Morocco	OCP (50%) – Morocco, Chambal (25%) and TCL (25%) – India	4.25 lakh MT phosphoric acid	Rock supplied by OCP at international price	Off take agreement by Chambal-TCL with OCP for off take of entire quantity of phos acid.
5.	Tunisia-India Fertilizer Company (TIFERT), Tunisia	GCT (Tunisia), CFL and GSFC (India)	3.60 lakh MT of phosphoric acid	Rock supplied by GCT at international price	Off take agreement by CFL-GSFC with GCT for off take of entire quantity of phosphoric acid.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न पूछने का आशय दूसरा था, शायद माननीय मंत्री जी समझ नहीं सके, क्योंकि उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह हम सबको ज्ञात ही है कि कितनी कमी है, कितनी डिमांड है। एक हर साल 5 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, जो किसानों के ऊपर जा रहा है। यह हमारा खुला आरोप है। मंत्री जी, अगर आप कहें, तो हम लिख कर दे सकते हैं, आप सीबीआई जांच करा लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपको सारे डाक्युमेंट्स दे दूंगा। मैंने दो पाट्र्स में प्रश्न किया है। एक तो यह है कि सरकार ने इस मुद्दे से निपटने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए। माननीय मंत्री जी, कदम उठाने से मतलब यह था कि जब से आपने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीसी) लागू की, डीएपी के दाम करीब-करीब तीना गुना बढ़ गए, 400 से 1200 रुपए हो गए, आपने उस दाम को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब 2010 में न्यूट्रिएंड बेस्ड सब्सिडी लागू की गई थी, तो उस समय शायद आपके डिपार्टमेंट ने इसका विरोध किया था, in writing. एक तो हम लोगों को दुख है कि जिस दिन क्वैश्चन डे होता है, उस दिन बड़े मंत्री जी बीमार हो जाते हैं। भगवान करे, वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन कभी-न-कभी हम लोगों को जबाव दे दें। वे आज तक जबाव ही नहीं दे पाए, हम लोग तरस गए।...**(व्यवधान)**... वे उर्वरक राज्य मंत्री हैं, मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, जब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लागू हुई थी, तो इफको और आईपीएल ने सरकार को लिख कर दिया था कि अगर आप इसको लागू कर देंगे, तो हम खाद के दाम नहीं बढ़ने देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि यह सही है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लागू होने के बाद, जो 2010 में लागू हुई, अब तक कितने दाम बढ़े? अगर आपके मंत्रालय ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का विरोध किया था, क्योंकि तत्कालीन मंत्री, जो मौजूदा मंत्री हैं, उन्होंने लिख कर दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तो फिर इसको लागू करने का कारण क्या था? अगर इससे दाम बढ़े, तो सरकार न्यूट्रिएंड बेस्ड सब्सिडी को वापस लेगी या नहीं?

श्री श्रीकांत जेना: सर, इसमें दो-तीन इश्यूज़ हैं। इनका जो मूल प्रश्न है, वह NPK Fertilizer के संबंध में है। NPK Fertilizer के लिए हमारी कंट्री विदेश पर निर्भर है, अपने देश में इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। 90% के करीब NPK Fertilizer हम विदेश से ही मंगाते हैं। NBS Policy 1 अप्रैल, 2010 को शुरू हुई थी। उस समय यह सोचा गया था कि कॉम्पिटीशन होने से प्राइज़ घटेगा और इंटरनेशनल प्राइज़ के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन वास्तविक चित्र यह है कि 2010 के बाद इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा है। इसके कारण दो चीज़ें हुई - एक तो एक्सेस रेट्स का ट्रेंड आया, विशेषकर लास्ट ईयर DAP का International Price 580 डॉलर तक चला गया। यह बात सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल पर NPK Fertilizer में एक बड़ा कार्टेल है। इस कार्टेल को तोड़ने के लिए भारत सरकार का यही प्रयास था कि ज्वाइंट वेंचर के तहत कम से कम हम अपने देश में कहीं अपना प्लांट लगा सकें, ताकि

भारत की यह डिपेंडेंसी कम हो सके। लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं।

जहां तक NBS Policy की बात है, हमने सोचा था कि NBS Policy आने के बाद प्राइस घटेगा, लेकिन उसका असर भी ठीक से नहीं आया। डिपार्टमेंट में Committee of Secretaries के लोग बराबर इसके कारणों का रिव्यू करते रहते हैं और बराबर वहां यह विचार किया जाता है कि इसमें क्या किया जा सकता है अथवा हमारी पॉलिसी में क्या गड़बड़ी है या क्या हम पॉलिसी में कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? डिपार्टमेंट में बराबर इन बातों का विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि since we are totally dependent on import, we have a very little role because the companies are fixing the MRP. The Government has no role under the policy in fixing the MRP. The Government has changed only this situation that fixed subsidy will be there. After the policy was in operation, the Government every year fixed the subsidy at a fixed price on the NPK. But in the urea sector, we are comfortable. The price has not been increased. The availability is comfortable. The availability of NPK fertilizer is also comfortable. The only question is that the price of NPK fertilizer has increased twofold in many areas which is a matter of concern and the Government is seriously thinking as to what possibly can be done to take necessary steps in this direction.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने काफी हद तक सही बात कही, लेकिन हमने जो बात पूछी थी, उसका जबाव नहीं आया। माननीय मंत्री जी से मैंने जो बात कही...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल तो पूछिए।

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। जब NBS पॉलिसी लागू होनी थी, तब क्या IFFCO और IPL ने आपके मंत्रालय को यह लिख कर दिया था कि अगर आप NBS लागू कर देंगे, तो हम दाम बढ़ने नहीं देंगे? दाम तीन-गुने बढ़ गए हैं, DAP 400 से 1200 हो गया, यहां हम यूरिया की बात नहीं कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, मैंने यह पूछा था, अगर यह बात सही थी तो क्या आपके मंत्रालय ने विरोध किया? यदि विरोध किया तो फिर वित्त मंत्रालय ने उसे लागू क्यों किया? एक तो आप मेरे इस प्रश्न का जबाव दीजिए।

दूसरा, मान्यवर...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप एक ही सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, अभी तो मैं पहले सवाल को ही पूरा कर रहा हूं।

श्री सभापति : पहला सवाल तो खत्म हो गया।

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं, श्रीमन्, उसका पूरा जबाव नहीं आया। हमें संरक्षण तो आप ही देंगे। जब उधर से पूरा जबाव नहीं आया, तभी मैं पूछ रहा हूं।

मंत्री जी, मेरा दूसरा सवाल है, हमने ज्वाइंट वेंचर की बात कही, उसमें हमने यह नहीं पूछा था कि आप विदेश में कितना ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर के बारे में पूछने का मेरा मतलब था, चूंकि आपने बताया था कि ज्वाइंट वेंचर के तहत हिन्दुस्तान में कारखाने लगेंगे, लेकिन एक कारखाना भी ज्वाइंट वेचर के तहत नहीं लगा, सब कुछ आपने विदेश में ही कर दिया।

अगर आपने उनसे यह एग्रीमेंट किया था कि हर साल हम आपसे इतना माल खरीदेंगे, तो कम से कम इसमें पांच साल का एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उस एग्रीमेंट में आपने रेट्स तय किए थे या नहीं किए थे? अगर पांच साल पहले आपने रेट्स तय किए थे, तो फिर लगातार रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं?

मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या IFFCO और IPL ने गवर्नमेंट के सारे शेयर वापिस कर दिए? यदि शेयर वापिस कर दिए तब तो PUC नहीं रह गई। जब PUC नहीं रह गई, तो फिर उनसे सीधे खरीदने का राइट आपको किसने दे दिया, तब टेंडर के माध्यम से क्यों नहीं खरीदा गया। जब मालिक खुद निजी संस्था हो गई, तो फिर...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नरेश जी, आप सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूं। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यहां 5000 करोड़ रुपये का गबन है। यह मेरा सीधा आरोप है, मैं बहुत कम आरोप लगाता हूं।

5000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का बोझ देश के किसानों पर डाला जा रहा है। उनको लूटा जा रहा है। इफको और आई.पी.एल. के एम.डी. लूट रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब दोनों कम्पनीज़ ने गवर्नमेंट के सारे शेयर्स वापस कर दिए, तो उनको सीधे खरीदने का ऑर्डर कैसे दे दिया गया, टेंडर के माध्यम से क्यों नहीं दिया गया?

श्री श्रीकांत जेना : सर, जहां तक पहला सवाल है कि क्या इफको और आई.पी.एल. (इंडियन पोटाश लिमिटेड) ने भारत सरकार को लिख कर दिया था कि अगर एन.बी.एस. लागू किया जाए, तो फर्स्ट ईयर में हम प्राइस इन्क्रीज़ नहीं करेंगे, तो इसका उत्तर यही है कि केवल इफको और आई.पी.एल. ही नहीं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ की जो एसोसिएशन है, उसने भी लिख कर दिया था कि अगर प्राइस इन्क्रीज़ होगी, तो यह पहले साल 10 परसेंट के अंदर ही रहेगी। अगर हम फैक्ट्स पर जाएं, तो पाएंगे कि पहले साल 2010-11 में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन 2011-12 में जो क्राइसिस हुई है और इसके बाद जो आया, तो इनका कमिटमेंट जो उसी ईयर का था, उसमें लगभग 10 परसेंट की इन्क्रीज़ हुई थी।

जहां तक इफको में गवर्नमेंट शेयर होने की बात है, तो इफको के कोऑपरेटिव लॉ में अमेंडमेंट होने के बाद इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिये, गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिये और गवर्नमेंट को पैसे भी वापस कर दिए। Since the cooperative law was amended, they were free to surrender their cess to the Government. That is how they became independent. जहां तक इम्पोर्ट का सवाल है — except यूरिया का इम्पोर्ट, जो चैनलाइज्ड होता है — भारत सरकार तीन कम्पनीज़ के माध्यम से यूरिया इम्पोर्ट करती है। इनमें से एक एस.टी.सी., दूसरी एम.एम.टी.सी. और तीसरी आई.पी.एल. हैं।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मैं यूरिया के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो डी.ए.पी. की बात कर रहा हूं।

श्री श्रीकांत जेना : डी.ए.पी. तो फ्री है।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : यूरिया के दाम तो ज्यादा बढ़े ही नहीं।...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीकांत जेना : जहां तक डी.ए.पी. और एन.पी.के. फर्टिलाइजर्स का सवाल है, वह ओ.जी.एल. में है। Anybody can import, anybody can sell in the market, subject to the availability and requirement of the Government. Therefore, there is no restriction that we have allowed only these companies. Any company can ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, ये सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**... अगर ये यहां गलत जानकारी देंगे, तो...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नरेश जी, अगर सवाल को खत्म करना है, तो...**(व्यवधान)**... नरेश जी, प्लीज़।...**(व्यवधान)**... देखिए, आपने सवाल पूछ लिया है। अब आप जबाव भी सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, अगर माननीय मंत्री जी...**(व्यवधान)**... सर, मैं नियम 60 के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए आपको नोटिस दे रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: If you want a detailed discussion, please give a notice.

श्री नरेश अग्रवाल : बाकी सदस्य क्वेश्चन पूछेंगे।...**(व्यवधान)**... लेकिन, मैं नियम 60 के अंतर्गत नोटिस जरूर दूंगा। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को छुपाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**... यह एक बहुत बड़ा घोटाला है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: If you want a detailed discussion, please give a notice. ...*(Interruptions)*... You can't make speeches like this. ...*(Interruptions)*... Dr. Ramalingam.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, so far as urea is concerned, the country is importing to the extent of 25 per cent of the total requirement. After that import, the Government provides a high subsidy on that. The highly subsidized urea is available in our country. As compared with Bangladesh and Pakistan, the prices of urea are very low in our country. Therefore, a lot of smuggling is going on. The subsidized urea is being smuggled out of our country. What steps has the Government taken to stop this kind of smuggling? Also, what steps have been taken to put a ban on export of fertilizers, produced by the private factories?

SHRI SRIKANT JENA: Sir, so far as urea is concerned, as compared to NK fertilizer price, urea is really cheap. The Government has deliberately subsidized the price of urea because the farmers use urea. Yes, there are reports that urea is being smuggled out from country because our urea is highly subsidized. We have written to the State Governments to see that this kind of smuggling is stopped. The State agencies, and also the Central agencies, are active on that. And, not only the urea is being smuggled out, the subsidized urea, meant for agricultural purposes, is also being diverted for the industrial purposes. There are serious complaints, from many States, that the subsidized urea is being used for industrial purposes. Of course, this needs to be investigated. We have written letters to the different State Governments in this regard. This really needs to be strictly monitored. We are asking the State Governments to take action in this regard because normally the practice is that we hand over the subsidized urea to the State Governments. Therefore, the distribution of that urea is in the hands of the State Governments. The monitoring is also in the hands of the State Governments. Monitoring is in the hands of the State Government. The State Governments need to actively stop this kind of a diversion. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is a very serious issue. The hon. Minister has made the factual situation known. But, unfortunately, he has not given any solution. The DAP and the NPK rates have gone three-fold, from Rs. 475/- to nearly Rs. 1,200/-. That means input cost of agriculture is going up and we are not getting remunerative price. To see that this situation is resolved once and for all, will the Minister take the initiative to have a consultation with the Minister for Agriculture, Finance Minister and also call the interested MPs, so that we can find a permanent solution to this problem? Mr. Chairman, Sir, please bear with me, every year, during the agriculture season, there are long queues in every State, sometimes lathi charge also. Sometimes, States blame the Centre and the Centre blames the States. This is

happening continuously. We need to find a solution, because, as he rightly said, we have to import 90 per cent. Prices are going up like anything. The subsidy portion is only limited. Keeping this in mind, will he call a meeting of all these concerned people at the earliest, so that this issue can be resolved on a long-standing basis?

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I fully agree with the hon. Member that prices have increased. Yes, it is not only Rs. 1,200/- but, sometimes, it is Rs. 1,300/- in different places. The prices of DAP and the complex fertilizer are a matter of concern for everybody. The Government is really serious. We want a way out as to how to really curb this. Therefore, as you have suggested, we can certainly take the advice of the Ministry of Agriculture on what steps need to be taken. We can, certainly, take that advice.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the answer shows the serious situation prevailing in our country. Hundred per cent of potash and ninety per cent of phosphate depends on import from foreign countries. At the same time, till the announcement of new Policy, there is no single new investment in fertilizer industry in our country. Public Sector Companies are compelled to close their urea plants. They are struggling for getting working capital for producing other types of fertilizers. My question is: Is the Government ready to reopen the closed urea plants of the PSUs, including FACT? I would like to know whether the Government is ready to consider the request for a new package for working capital from the PSUs like FACT and other companies.

SHRI SRIKANT JENA: Sir, as you know, FCIL and HFCL closed about eight units in 2002. Now, we are importing about 25 per cent of the urea. The new Urea Policy has been announced recently. After this announcement, there are about 15 existing plants which have applied to the Department to expand their existing units. I am sure if those 15 existing plants, which have applied, are allowed to proceed, then, we will be self-sufficient by 2016 on the urea front. Production of urea depends upon the availability of gas. Therefore, because of the non-availability of gas, naphtha-based units are causing huge drain to the State Exchequer. As you know, in the case of naphtha-based units which are producing urea, the cost is Rs. 45,000/- per tonne, whereas, the gas-based unit's cost is hardly Rs. 25,000/- per tonne. The only thing is if the gas is available for urea production, then, I am sure, not only will we be self-sufficient, but we will also be able to export urea to other countries too.

MR. CHAIRMAN: Question No. 63. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : सर, खाद का मामला है...**(व्यवधान)**... देश के किसानों को लूटा जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : रूपाला जी, कृपया आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : सर,...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Give a notice, please.. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : नहीं, नहीं, सर...**(व्यवधान)**... देश में किसानों को लूटा जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, a notice will be given after the Question Hour. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: A notice is being given for a discussion on this. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Sorry; I can take only three questions. ...*(Interruptions)*... Question No. 63. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is such an important issue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Venkaiahji, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not asking for time. ...*(Interruptions)*... I have a right to know, when the House is agitated, where the concerned Minister is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Venkaiahji, you know the procedure. If a Minister takes permission to be absent...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Has he taken permission?

MR. CHAIRMAN: Yes, he has.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: To be absent from the House permanently!

MR. CHAIRMAN: No. ...*(Interruptions)*... Permission is for the sitting only. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : सर, किसानों को लूटा जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, there is an important question coming up. Please, बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... खन्ना जी, अपने पड़ोसी से जरा गुजारिश कीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, या तो जेना जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए या कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाइए।...**(व्यवधान)**... सर, कैबिनेट मिनिस्टर कभी नहीं आते।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nareshji, you have had your say. ...*(Interruptions)*... You have had your say. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं। नरेश जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... Mr. Rajeeve, please. You have had your say. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Question No. 63. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : *

MR. CHAIRMAN: No purpose is being served by this. Please allow Mr. Avinash Khanna to ask his question. ...*(Interruptions)*... Mr. Rajeeve, please. You have asked your question. ...**(व्यवधान)**... वे बैठ गए, अब आप भी बैठ जाइए।..**(व्यवधान)**...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : *

श्री सभापति : देखिए, none of this is going on record. What is the point? बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... Mr. Rajeeve, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please. Please.

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : *

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : *

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. This is not going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: *

MR. CHAIRMAN: What is the purpose of this? ...*(Interruptions)*... What is the purpose? ...*(Interruptions)*... Mr. Rajeeve, you have asked your question. This is not fair. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: *

---

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: You have asked the question. That question is over now. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: *

MR. CHAIRMAN: No; I am sorry. ...*(Interruptions)*... I am sorry. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: *

MR. CHAIRMAN: Please. The question is over. We are now on to Question No. 63. Please.

Closure of engineering institutions

*63. SHRI AVINASH RAI KHANNA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of engineering institutions in the country along with the details such as the number of seats, the number of students and the courses offered therein;

(b) the rate of placement in these institutions;

(c) whether about 150 such institutions from all over the country have applied to get permission for closure;

(d) if so, the steps Government is taking in this regard; and

(e) the number of students and others like teachers in these institutions?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.M. PALLAM RAJU): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are 3028 institutions conducting Diploma level programs, 3357 institutions conducting Under Graduate programs, 1901 institutions conducting Post Graduation programs and 54 institutions conducting Post Diploma programs in Engineering and Technology. The details of approved intake in All India Council for Technical Education (AICTE) approved engineering and technology institutions are given in the Statement-I (*See* below).

(b) The data regarding rate of placement is not maintained by the Ministry of Human Resource Development.

---

*Not recorded.